

संतुलित फैसला

समवार को मुख्य न्यायाधीश बीआर गवेई और न्यायमूर्ति आंगस्टाइन जॉर्ज मसीह की पीठ ने वक्फ सशोधन अधिनियम 2025 पर अपने अंतरिम फैसले में पूरी तरह रोक लगाने से इंकार कर दिया, लेकिन साथ ही कहा कि अंतिम निर्णय आने तक कुछ प्रावधानों पर रोक रहेगी। पीठ ने यह भी कहा कि अदालतों को संसद द्वारा बनाए गए कानून की वैधता माननी चाहिए और केवल दुर्लभतम मामलों में ही स्थगन देना चाहिए। 22ई और को अदालत ने अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं (जिनकी संख्या सी से अधिक है) के एक समूह पर अंतरिम रोक लगाने के अनुरोध पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने इन याचिकाओं पर गहनता से विचार किया और पाया कि कानून के संपूर्ण प्रावधानों पर रोक लगाने का औसत मामला नहीं बनता, लेकिन पीठ ने यह भी माना कि कुछ धाराओं को कुछ संरक्षण की आवश्यकता है। जैसे पीठ ने कहा कि कलेक्टर को नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों का न्याय निर्णय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पीठ ने साफ कहा कि अगर ऐसा होता है तो शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन होगा। ठीक इसी तरह पीठ का यह भी कहना था कि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में क्रमशः 22 और 11 सदस्यों में से तीन से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए। हालांकि ऐसा कहते हुए यह भी साफ किया कि यह न्यायालय कोई निर्देश जारी नहीं कर रहा है। फिर भी उचित यही होगा कि पीठ ने पांच साल तक इस्लाम का पालन के मानदंड के कार्यान्वयन पर भी रोक लगा दी। ऐसा करते हुए पीठ का कहना था कि जब तक नियम नहीं बन जाते तब तक वक्फ संपत्ति घोषित होने से पहले इस पर रोक रहेगी। पीठ का मानना है कि बिना किसी तंत्र के यह मनमाने शक्ति के प्रयोग को बढ़ावा देगा। अब अंतराल तबतक तो तभी साफ होगी जब पीठ का संपूर्ण फैसला आएगा, लेकिन फिलहाल आए फैसले से सभी पक्ष संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। जहां केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने उच्चतम न्यायालय के वक्फ अधिनियम 2025 पर आए निर्णय का स्वागत किया है और इस निर्णय को लोकतंत्र के हित में बताया है वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारी समि. के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने भी पीठ के फैसले की सराहना की है और कहा है कि वे उच्चतम न्यायालय द्वारा मुस्लिम पक्ष की दलीलों को स्वीकार करने के आदेश का स्वागत करते हैं और उम्मीद जताई कि इस मामले पर पूरा फैसला आने पर मुसलमानों को पूर्ण राहत हासिल होगी। उन्होंने यह भी कहा कि हमें उम्मीद थी कि पूरे एकट पर स्टे लिया जाएगा, लेकिन कुछ अहम बातों पर स्टे लिया गया, जिसका वह स्वागत करते हैं। उनके अनुसार अभी पूरा फैसला आना बाकी है, उम्मीद करते हैं कि हम रिलीव हासिल होगी। निश्चित रूप से कोर्ट को जो अंतरिम फैसला आया है वह बेहद संतुलित है और तर्कसंगत भी है, जबकि सरकार की भाषा से लुहा है कि वह फैसले से इतनी खुश नहीं है और वह यही दुहाई दे रही है कि संसद के पास कानूनों में अदालतों को ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

...तो सिख कैसा महसूस करेंगे

वक्फ संशोधन अभिनियम पर सुप्रीम कोर्ट का यह अंतरिम आदेश है, हम उम्मीद करते हैं कि शीघ्र कोर्ट इस पर कानून पर जल्द अंतिम फैसला सुनाए और सुनवाई शुरू हो, सीओ को नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह व्यक्ति जहां तक संभव हो मुस्लिम होना चाहिए, अब सरकार यही कह रही कि उन्हें कोई योग्य मुस्लिम नहीं मिला, जो पाठों किसी मुसलमान को सांसद का डिकेट नहीं देती, जिसके पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, क्या वह मुसलमान अधिकारी चुनेंगे? खुफिया विभाग में कितने मुसलमान अधिकारी हैं, वे वक्फ में चर्चा मुसलमानों को नियुक्ति करेगे, यह संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है, शिरोमणि शुद्धरा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) में किसी गैर-सिख को सदस्य बना दिया जाए तो सिख कैसे महसूस करेंगे।

—असदुद्दीन ओवैसी, प्रमुख, एआईएमआईएम



ने पाल के अंतरिम सरकार की नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने पदभार ग्रहण करने के बाद मातहतों के साथ संक्षिप्त बातचीत में साफ कर दिया है कि वे सत्ता का स्वाद चखने नहीं आई हैं। 'हह' महीने बाद होने वाले चुनाव के बाद वे नए परिनिधि सभा को सत्ता की चाभी सौंप देंगी। हां इस दौरान उनकी पूरी कोशिश होगी कि नेपाल अब सत्ता के लिए और ईमानदार सरकार के युवाओं को। इसके साथ संघर्षशील व ईमानदार युवाओं को आगे आना होगा।

उन्होंने जो दूसरी बड़ी बात कही वह नेपाल को तहस-नहस करने वालों की शिनाख कर उन्हें सजा-दिलाने का। सुशीला कार्की के लिए यह बड़ी चुनौती है, क्योंकि आंदोलन तो जेन जी के हाथ में था और उन्होंने को सहमत से वह प्रधानमंत्री बनी हैं तो क्या जेन जी के आंदोलन में दूसरे लोग भी घुस आए और देखते देखते नेपाल को लोख में तब्दील कर दिया? ये दूसरे लोग आखिर कौन हो सकते हैं? इसे लेकर कायसबाजी का दौर जारी है। हर जुबान पर अलग-अलग चर्चाएँ हैं। अब अगर जेन जी के आंदोलन में भारी संख्या में उपद्रवी घुस आए और काठमांडू से लेकर नेपाल के मैदानी इलाकों तक आंदोलन को हिंसात्मक बना दालें तो यह मानना होगा कि वे कितने मुस्तैद थे? प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के नेतृत्व का मौजूदा प्रशासन इन उपद्रवियों की शिनाख कैसे से और किस आधार पर करता है यह देखने वाली बात होगी। भारी हिंसा के बीच पदासीन हुई सुशीला कार्की के समक्ष सिर्फ यही चुनौती नहीं है, देखें तो उनके समक्ष चुनौतियाँ का पहाड़ हैं। उम्मीद है कि इस समक्ष बावजूद वे जले बिखरे और टूटे फूटे नेपाल को नया जीवन दे पाने में कामयाब होंगी। सुशीला कार्की न्याय विद के साथ एक राजनीतिस्त परिवार से जुड़े रहने के नाते वे परिपक्व राजनीतिस्त भी हैं। इसकी झलक तब देखने को मिली जब जेन जी के तरफ से उनका नाम फाइनल होवे के बाद भी वह प्रधानमंत्री बनने को लेकर हड़बड़ी में नहीं दिखीं। प्रधानमंत्री पद की शायश उन्होंने तभी ली जब राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल को संसद विघटन की उनकी मांग को मानना पड़ा। सुशीला कार्की के इस बात की सभी कायल हुए तो फिर पुराने प्रतिनिधि सभा का ही नेतृत्व करना है तो प्रष्ट्यार जिसके खिलाफ इतना बड़ा आन्दोलन हुआ, उससे पर पापा संभव नहीं है। उन्होंने दो टुक करवा किए वह एक प्रष्ट सरकार का नेतृत्व नहीं करना चाहेंगी।

सुशीला कार्की के पति दुर्गा प्रसाद सुवेदी का ताल्लुक नेपाली कांग्रेस से थे जिन्हें स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइराला का नजदीकी माना जाता है। दुर्गा प्रसाद सुवेदी पर 1973 में रायल नेपाल के जहाज

भविष्य में ऐसे विद्रोह की पुनरावृत्ति को रोकने और शासन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए स्वतंत्र एंटी कर्षण कमीशन बनाना जाए जो राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त हो। साथ ही करेट नेताओं पर मुकदमे चलाए जाएं। रोजगार सृजन हेतु युवा केंद्रित नीतियां –आईटी हब, कृषि सुधार अपनाए जाएं। एमसीसी ग्रांट को पारदर्शी तरीके से उपयोग में लाया जाए। साथ ही राजनीतिक स्थिरता हेतु चुनाव सुधार और राजनीति में युवाओं को शामिल किया जाए। इस समय नेपाल को अंतर्राष्ट्रीय सहायता की नितांत आवश्यकता है।

नेपाल: सुशीला कार्की के समक्ष चुनौतियों का पहाड़



के अपहरण का भी इल्जाम है। हालांकि यह एक आंदोलन का हिस्सा थे। इस घटना पर उनको एक पुस्तक की खूब चर्चा रही। बहरहाल सुशीला कार्की के पति का नेपाली कांग्रेस से ताल्लुक होने का कोई छाप इन पर नहीं है और न ही नेपाली जहाज के अपहरण से ही उनका कोई लेना देना रहा। वह तब भी अपनी मर्जी की मुछ्ता रही और आज भी। बतौर न्यायाधीश उनके कई फैसले चर्चा में रहे जिसमें नेपाली कांग्रेस के एक मुस्लिम नेता के खिलाफ फैसला राजनीतिक गलियारों में भूचाल जैसा था। उनको जो कार्यशैली और दृढ़ इच्छाशक्ति है निःसंदेह नेपाल को उसका फायदा मिलेगा। यद्यपि कि समय कम है, छह महीने बाद होने वाले चुनाव का परिदृश्य क्या होगा, इस पर कुछ भी कयासबाजी ठीक नहीं है। आगामी चुनाव को लेकर भारत विरोधी और भ्रष्टचम सरकार का नेतृत्व करने वाले कई शर्मा आंली को सत्ता से उखाड़ फेंकने वाले जैन जो के नीजवानों का खूब भी स्पष्ट नहीं है। वह अलग कोई राजनीतिक दल गठित करंगे या मौजूदा किसी दल के साथ आधुनिक, यह भी तय नहीं है। भविष्य के नेपाल में साफ-सुथरी सरकार के लिए उन युवाओं का राजनीतिकरण जरूरी है। बेहद कम समय में सुशीला कार्की के समक्ष नेपाल को फिर से सजाने संवारने की चुनौती भी है। आगजनी और तोड़फोड़ में नेपाल को अरबों-खरबों का नुकसान हुआ है। नेपाल को फिर से बनाने में इतनी बड़ी रकम जुटाना आसान नहीं है। इसके लिए कोन-कोन देश अगर आता है, यह काफी कुछ उन सरकार के विदेश नीति पर निर्भर करेगा। दूरिस्ट जो नेपाल के आर्थिक स्रोत का बड़ा जरिया है, उसे

स्थापित करना भी बड़ी चुनौती है। नेपाल यू.एन. आंदोलनों का देश है। सबसे भयावह आंदोलन लोक कर्तव्य बहाली को लेकर था, जिसे जनयुद्ध के नाम पर सै भी जाना जाता है, उसमें जनहानि खूब हुई लेकिन सरकारी इमारतों को क्षति नहीं पहुंचाई गई थी। बीच बीच में और भी तमाम आंदोलन हुए लेकिन वे इतना भयाक्रांत नहीं रहे। इस बार के आंदोलन की भयावहता देख भारत सहित अन्य देशों के दूरस्थों का रुख नेपाल की ओर होने में वक़्त लगेगा। काठमांडू में भारतीय पत्रकारों को चुन-चुन कर मारा गया यह जानते हुए कि जले धुने नेपाल के पुनर्निर्माण में भारत ही मुख्य सहायक होगा। दरअसल यह सब भारत के प्रति ओली सरकार द्वारा बोए गए जहर का ही अंश था। कुछ वर्ष पूर्व आए भूकंप से नेपाल में जितनी तबाही नहीं हुई थी, नेपाली युवाओं ने अपने हाथों से नेपाल को उससे बड़ी त्रासदी दे दी। जितनी किन्मथी थी, उसे हटाने के लिए आंदोलन ठीक था, लेकिन सरकारी संपत्तियों को सुपुर्द-ए-खाक करना नादानी थी। काठमांडू से लेकर नेपाल के तमाम शहरों कस्बों में जलते हुए मकान, सरकारी इमारतों को देख ऐसा लगता है कि इसका पुनर्निर्माण आसान नहीं है। हर जुवान पर चर्चा है कि अब परंप्रतिनाथ ही नेपाल को नया जीवन दे पाएंगे। सुशीला कार्की की जित भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल बनाने के साथ भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति की भी है। नेपाल में अभी जितने भी राजनीतिक दल हैं, उसके सारे बड़े नेताओं के हाथ भ्रष्टाचार से सने हैं, चुनौती है राजनीति से भ्रष्टाचार खत्म करना भी बड़ी चुनौती है। राजधानी काठमांडू जिससे काष्टमंडप भी कहा जाता था, अब स्वाहा हो चुका है। मात्र 48 घंटे की अराजकता में अब स्वाहा हो बर्बाद हो गया। सरकार और विपक्ष भाग खड़े हुए। भ्रष्टाचार को अपनी जान बचाने को इधर-उधर भागना पड़ा। उन्हे घर के पिछवाड़े, नदी नालों के कद कर भागते हुए देखा गया। आंदोलनकारियों के पैरों में जो आए उनकी जमकर कुटाई हुई। युवाओं में सरकार हो या विपक्ष सभी नेताओं के प्रति ऐसा गुस्सा था कि चाहे संसद भवन हो या राष्ट्राध्यक्ष कार्यालय, सिंह दरबार हो या रेब्यू भवन सभी में आग लगा दी गई। सारे जरूरी दस्तावेज



जल्दकर स्वाहा हो गए। जेलों से भारी संख्या में कैदी फरार हो गए। पूर्व प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, दर्जनों मंत्रियों के आवास फूंक दिए गए। भारत नेपाल संबंधों को नया आयाम देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री गिरिजा नेपाल का गांधी भी कहा जाता है, स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइराला की प्रतिमा पर वीरगज में बरस रही हथौड़ा चलाते दृष्टा देखा गया। इधर जेन जी समूह में इस बात को लेकर वैचारिक मतभेद भी था कि अंतरिम सरकार को नेतृत्व धर्मनिरपेक्ष विचारधारा का हो या राज संस्था विचारधारा का? सुशीला कार्की की शिक्षा वागणसी के बीएचयू में भी हुई है और यह भारत के प्रधानमंत्री को फालो करती हैं। जेन जी समूह के 40 प्रतिशत से अधिक कर्मी हैं। जेन जी पहली पदवी थीं। जेन जी का यह सहो फैसला था कि उन्होंने एक साहसी न्यायविद महिला को अंतरिम सरकार का मुखिया चुना। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला न्यायाधीश थीं, अब पहली महिला प्रधानमंत्री का खिताब भी उनके खाते में दर्ज हुआ। राजशही के जमाने से ही नेपाल का भारत से उतार-चढ़ाव जैसा संबंध रहा है। लोकतंत्र का बहारी के बाद ज्यादातर नेपाली सरकारें भारत से मतलब भर का संबंध रखती थी। अभी अभी तत्कालपलट के शिकार हुए ओली की शिनाख्त कट्टर भारत विरोधी की रही है। उन्होंने नेपाल की जनता में भारत के खिलाफ जहर घोलने में कोई कसर नहीं छोड़ा। सत्ता से हटने के बाद भी सेना के कैप्टन कपुर्न से उन्होंने तत्कालपलट के लिए मनागढ़त चहानियों के साथ भारत पर आरोप मढ़ा है। भारत नेपाल के बीच असमहमियाँ हैं, इसे लेकर प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का क्या रुख होता है, यह भी गौरतलब होगा। सनातनी विचारधारा से लैस पूर्व न्यायाधीश सुशीला कार्की के हाथ नई सरकार की कमान भारत के लिए सुखद संकेत है। इस बात की कामना की जानी चाहिए कि सुशीला कार्की को नेतृत्व में नेपाल में लोकतंत्र मजबूत हो और वह फिर से उठा खड़ा होने में सक्षम हो।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

नेपाली युवाओं के आक्रोश का असर



डा. चंद्रप्रकाश शर्मा

युवा शक्ति का पुंज है, भुजदंडों में जाना। मेधा से सम्पन्न व्यक्त, रत्नतनू विधान। युवा उल्ट है वायु का, अंधड़ न बन जाए, इसकी मेधा -शक्ति का सभी करो समाज। ये पंक्तियां 8 सितंबर 25 को नेपाल की सड़कों पर उठने युवाओं के विरोध प्रदर्शन की सीटीका को उद्घाटित करती हैं। हिमालय की गोम में बसा एक छोटा सा देश नेपाल आज एक अभूतपूर्व राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है। जिस जरेजरेश-जी विद्रोह के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि इस विद्रोह में जरेजरेश-जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जरे-जी नेपाल की आबादी का लगभग 30 प्रतिशत हैं। जेन-जी वह आबादी है जिसका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है। 4 सितंबर 2025 को ओली सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया, जिससे युवाओं ने अस्थायित्व की स्वतंत्रता पर हमला माना जबकि सरकार ने इन प्लेटफॉर्म को फेक न्यूज फैलाने और विदेशी हस्तक्षेप

का दोषी ठहराया। हमी नेपाल संगठन के लीडर व सामाजिक कार्यकर्ता सुन्द गुरुंग ने सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ युवाओं को एकजुट कर आंदोलन खड़ा किया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ सोशल मीडिया प्रतिबंध का मुद्दा नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और अक्षम शासन के खिलाफ लड़ाई है। इससे युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा क्योंकि ओली सरकार पर भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हैं और विगत वर्षों में सड़क निर्माण और बिजली परियोजनाओं में अरबों का घोटाला सामने आ चुका है। साथ ही युवा वर्ग पहले से ही शासन वर्ग के परिवारों को ठेके और नीकरियों में प्राथमिकता देने से नाराज था।

इसक साथ ही 2024 में अलि सकारा बड़ा दो बार गठबंधन बनने से राजनीतिक स्थिति बढ़ा और सत्ता परिवर्तन की जगह का विचारस लोड़ा। रैपर से मेयर बने बालेन शाह ने फेसबुक पर जेन - जी के नेतृत्व में शुरू हुआ आंदोलन को समर्थन किया। बालेन, प्रष्ट्याचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के कारण नेपाल के युवाओं में बहुत अधिक लोकप्रिय हैं। आर्थिक असमानता और बेरोजगारी के कारण नेपाल के युवा व्रत हैं, उनके अर्थव्यवस्था में के गुस्से को बल मिला। नेपाल का अर्थव्यवस्था अर्ध-अस्थिर प्रवासी नेपाली नजदूरों से आने वाला धन, पर निर्भर है, यह व्यवस्था पटरी पर नहीं लौटी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों के और पलायन बढ़ा है, लेकिन युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही हैं,

जबकि नेताओं के परिवार लगातार अमीर हो रहे हैं। बुनियादी ढांचे में निवेश कम है। जरूरतें—जो को लागू किया कि विकास का मॉडल टूट चुका है, इस विचार ने विविध प्रदर्शनों में ईंधन का काम किया। इसके साथ ही हिंदू राज और राजशाही समर्थक समाजवादी भी एक कारक बनने को लगा कि हमारी समाज और सांस्कृतिक पहचान खोती जा रही है। इन कारणों ने एक जटिलमूर्खी का रूप धारण कर प्रदर्शन को हिंसक बनाया जिससे 1990 के दशक को मृत्यु हो चुकी है, रैकेटों द्वारा घायल हैं, संसद भवन, प्रधानमंत्री आवास और अन्य सरकारी इमारत में आग लग गई। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को त्यागपत्र देना पड़ा। विद्रोह को रोकना समय की मांग है। संसद को मृत्यु यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन संकट से उबरने के लिए हमें सार्थक उपाय करने होंगे ताकि वर्तमान संकट को शांत करके भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। इस हेतु तात्कालिक रूप से सेना को राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रहकर अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक को आमंत्रित कर संवाद शुरू करना चाहिए। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध हटा लिया गया है लेकिन एक न्यूज पर नियंत्रण के लिए पारदर्शी नीति बनाने जानी जाएगी। साथ ही बेरोजगारी को आर्थिक राहत देने हेतु बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था हो। पर्यटन को पुनर्जीवित किया जाए तथा विषय बैंक से आपातकालीन फंड मांगे जाएं, ताकि नेपाल की अर्थव्यवस्था और निर्माण को पटरी पर लाया जा सके।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

ओजोन परत के बिना असंभव पृथ्वी पर सुरक्षित जीवन का अस्तित्व

1 6 सितम्बर 1987 को मॉन्ट्रियल में ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए एक अंतराष्ट्रीय समझौता हुआ था, जिसमें उन रासायनों के प्रयोग को रोकने से संबंधित एक बृहद महत्वपूर्ण समझौता किया गया था, जो ओजोन परत में छिद्र के लिए उत्तरदाई माने जाते हैं। ओजोन परत को रोकने है, यह किन्तु तेजी से कम हो रही है और इस कमी को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसी संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए 1994 से प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस मनाया जा रहा है किन्तु निम्ना की बात यह है कि पिछले कई वर्षों से ओजोन दिवस मनाए जाते रहने के बावजूद ओजोन परत की मोटाई कम हो रही है।

प्रतिपाद एक विशिष्य थीम के साथ यह महत्वपूर्ण दिवस माना जाता है। विश्व ओजोन दिवस 2025 को थीम विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक है, जिस से संयुक्त राष्ट्र ने जारी किया है। यह थीम ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोकॉल के 40 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ओजोन परत के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विज्ञान की भूमिका और आवश्यक वैश्विक सहयोग पर केंद्रित है।

विश्व ओजोन दिवस हमें स्मरण कराता है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत आवश्यक है और यह ध्वनि निरंतर भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसे बचाने हेतु निषेध जलवायु कार्रवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। आईपीसीसी की एक रिपोर्ट में तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की स्थिति को आकलन करने किए जाने के बाद से वृद्धि डिग्री तक सीमित रखने की आवश्यकता महसूस की जा रही है और इसके लिए

विश्व ओजोन दिवस पर विशेष

युनिभाषर के देशों से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के रूप लक्ष्य निर्धारित करने की अपेक्षा को कम कर रही है। जहां तक भारत की बात है तो भारत ने 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को तीव्रता में 35 प्रतिशत की दर से कम करने का लक्ष्य रखा है किन्तु जी-20 देशों पर जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों की समीक्षा पर आधारित एक रिपोर्ट में कुछ समय पहले कहा गया था कि भारत सहित जी-20 देशों ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, वे ताम्पान वृद्धि को डेढ़ डिग्री तक सीमित करने के दृष्टिगत पर्याप्त नहीं हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल अखति परमाणु हासिल करने के लिए इन देशों को अपने उत्सर्जन को आधा करना पड़ेगा। रिपोर्ट में इस बात पर भी चिंता व्यक्त की गई थी कि पिछले जू-20 देशों की जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होनी चाहिए। वहीं 82 फीसदी जीवाश्म ईंधन ही इस्तेमाल हो रहा है और चिंताजनक रूप से जीवाश्म ईंधन की मांग भी 82 फीसदी के कुछ देशों में जीवाश्म ईंधन की मांग पर सिब्बिटी भी दी जा रही है। भारत ने हरित ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य 2027 तक 47 फीसदी बढ़ा दिया है और 2030 तक सी फीसदी इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन का भी लक्ष्य है। हालांकि नवीन ऊर्जा के इन लक्ष्यों के अतिरिक्त रिपोर्ट में भारत की सहजता भी की गई थी। विश्वभर के अधिकांश क्षेत्रों में आज जलवायु परिवर्तन के चलते विभिन्न शा की जो दौर देखा जा रहा है, उसके लिए काफी

हद तक ओजोन परत की कमी मुख्य रूप से जिम्मेदार है और हमें अब यह भी भली-भांति समझ लेना चाहिए कि हमारी लापरवाही और पर्यावरण से बड़े पैमाने पर खिलवाड़ की पर्यावरण विनाश की सबसे बड़ी जड़ है। कुछ समय पूर्व एक रिपोर्ट में कहा गया था कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के चलते दुनियाभर में करीब 12 करोड़ लोग विस्थापित होंगे। ओजोन परत के सुरक्षित न होने से मनुष्यों, पशुओं और यहां तक की वनस्पतियों के जीवन पर भी बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है। यही नहीं, अंधकृषि पैदाशानियों का मानना है कि ओजोन परत के बिना पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा और पानी के नीचे का जीवन भी नहीं बचेगा।

हिन्दी अकादमी दिल्ली के सौजन्य से पर्यावरण छपी चर्चित पुस्तक प्रदूषण मुक्त सांसें के मुताबिक ओजोन परत की कमी से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता सर्दियां अनियमित रूप से आती हैं, हिमखंड गल



शुरू हो जाते हैं और सदी की तुलना में
गर्मी अधिक पड़ती है, पर्यावरण
का यही हाल पिछले कुछ वर्षों
से हम देख और भुगत भी रहे
हैं। दरअसल ओजोन परत में कमी
और मोटे होते जा रहे छिद्र के कारण
पृथ्वी तक पहुँचने वाली पराबैंगनी
किरणें हमारे स्वास्थ्य तथा पारिस्थितिकी
तंत्र पर बहुत हानिकारक प्रभाव
डालती हैं। ओजोन परत की
कमी से हमारे स्वास्थ्य के
लिए गंभीर खतरें उत्पन्न
हो रहे हैं। ओजोन परत
वातावरण में बनती है
जब सूर्य से पराबैंगनी
किरणें ऑक्सीजन
परमाणुओं को तोड़ती
हैं और ए परमाणु
ऑक्सीजन के साथ मिल
जाते हैं तो ओजोन अणु
बनते हैं। ओजोन परत पृथ्वी
के धरातल से 20-30 किमी
की ऊँचाई पर वायुमण्डल के समतापीय
मंडल क्षेत्र में ओजोन गैस का एक झोला सा आवरण है।
यह परत पर्यावरण की रक्षक मानी गई है क्योंकि यहीं
वह परत है, जो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से
रोकती है। हमारे ऊपर के वातावरण में विभिन्न परतें
शामिल हैं, जिनमें एक परत स्ट्रेटोस्फियर है, जिसमें



योगेश कुमार गोयल

ओजोन परत भी कहा जाता है। ओजोन गैस प्राकृतिक रूप से बनती है। निम्नले वातावरण में पृथ्वी के निकटतम ओजोन की उपस्थिति प्रदूषण बढ़ने वाली ओजोन स्थायिक के लिए हाहनाकार लेकिन ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत की उपस्थिति पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए अत्यावश्यक है। जब सूर्य की किरणें वायुमंडल में ऊपरी सह पर ओक्सीजन से टकराती हैं तो उच्च ऊर्जा विकिरण के कारण इसका कुछ हिस्सा ओजोन में परिवर्तित हो जाता है।

ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों के लिए एक अच्छे फिल्टर के रूप में कार्य करती है। सूर्य विकिरण के साथ आने वाली पराबैंगनी किरणों का लगभग 99 फीसदी भाग ओजोन मंडल द्वारा सोख लिया जाता है, जिससे पृथ्वी पर रहने वाले प्राण जीव वनस्पति सूर्य के तेज ताप और विकिरण से सुरक्षित हैं और इसी कारण ओजोन परत को सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। यही कारण है कि प्रायः कहा जाता है कि ओजोन परत के बिना पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व ही सम्भव हो जाएगा।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

